(राजेश बिंदल, जे.)

राजेश बिंदल और हरिंदर सिंह सिद्धू से पहले, जेजे

प्रेम याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और-प्रतिवादी 1996 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8079

20 जनवरी, 2017

भूमि अधिग्रहण अधिआदेश, **1894-धारा. 18** और **28-**ए-याचिकाकर्ता द्वारा **भूमि अधिग्रहण -17.03.1986** अधिग्रहित भूमि-एल. ए. सी. द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ता आपत्तियां दायर नहीं कर सका-अन्य भूमि मालिकों ने आपत्तियां दायर कीं जिन्हें अदालत में भेजा गया था-अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने **अनुदान दिनांक 30-11-1991** का मूल्यांकन किया-याचिकाकर्ता ने अन्य भूमि मालिकों को दिए गए समान मुआवजे के लिए अधिआदेश की खंड **28-**ए के तहत आवेदन दायर किया-कलेक्टर ने **09.04.1993 के** आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि संदर्भ अदालत का **अनुदान** उच्च न्यायालय में चुनौती के तहत था-याचिकाकर्ता ने **09.04.1993 के आदेश को चुनोति देते हुए** रिट याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि खंड **28-**ए केवल उन भूमि मालिकों को अधिकार देने के लिए अधिआदेश में डाली गई थी जिन्होंने अधिआदेश की खंड **18** के तहत आवेदन दायर नहीं किया था-कलेक्टर के लिए सही मार्ग रखना था **ताकि आवेदन अधिआदेश 28(A) धारा को मामले के उच्च न्यायलय व सर्वोच्च न्यायलय अंतिम आदेश तक लंबित रख सकें |**

अभिनिर्धारित किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.1993 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अधिआदेश की खंड 28 ए (1) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन केवल इस कारण से दायर किया गया था कि संदर्भ न्यायालय का निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए भरोसा किया गया था, इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय था।ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नोएडा

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2009 (1) एस. सी. सी. 754 में अच्छी तरह से समझाया गया है।न्यायालय द्वारा व्यक्त राय यह है कि ऐसी स्थिति में कलेक्टर अधिनियम की खंड 28 ए के तहत आवेदन को तब तक लंबित रखने की अपनी शक्ति के भीतर होगा जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(पैरा 11)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त कानून की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, इस परिस्थिति में कलेक्टर के लिए सही तरीका यह था कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की खंड 28 ए के तहत दायर आवेदन को तब तक लंबित रखा जाए जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता।

(पैरा 13)

सोमनाथ सैनी, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

अंकुर मित्तल, एडिशनल।महाधिवक्ता हरियाणा।

राजेश बिंदल, जे।

(1) याचिकाकर्ता ने भूमि संलग्नक अधिआदेश दिनांकित 09.04.1993, 1894 की खंड 28 ए के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन (संक्षेप में 'अधिआदेश') को इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया था कि संदर्भ न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील इस न्यायालय में लंबित थी और संदर्भ न्यायालय के फैसले, जिस पर भरोसा किया गया था, को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।अनुलग्नक 3 पी5 दिनांकित 09.02.1995 को भी चुनौती दी जा रही है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में विवाद के संदर्भ के लिए दायर आवेदन 'दायर' किया गया था।आगे की प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2 को विवाद को न्यायालय में भेजने के लिए अधिनियम की खंड 28 ए (3) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन अनुलग्नक 3 पी4 का निपटारा करने का निर्देश दिया जाए ।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि को अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना 23.5.1983 के माध्यम से राज्य द्वारा अधिग्रहित करने की मांग की गई थी। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (संक्षेप में 'कलेक्टर') ने 17.3.1986 पर 48000/3 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा की।याचिकाकर्ता आपत्तियाँ दायर नहीं कर सका, हालाँकि, अन्य भूमि मालिकों ने आपत्तियाँ दायर कीं जिन्हें अदालत में भेजा गया था।विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार ने 30.11.1991 दिनांकित निर्णय के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के लिए 100/3 प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे का आकलन किया।याचिकाकर्ता ने अधिनियम की खंड 28 ए के तहत वही मुआवजा देने के लिए आवेदन दायर किया जो अन्य भूमि मालिकों को दिया गया था।कलेक्टर द्वारा इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि संदर्भ न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।यहां तक कि इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा विवाद को अदालत में भेजने के लिए दायर आवेदन भी 'दायर' किया गया था।प्रतिवादी की कार्रवाई का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि खंड 28 ए को अधिनियम में केवल उन भूमि मालिकों को जिन्होंने अधिनियम की खंड 18 के तहत शुरू में कोई आवेदन दायर नहीं किया था, उन्हें न्यायालय द्वारा दी गई राशि के संदर्भ में मुआवजे के पुनर्निर्धारण की मांग करने का अधिकार देना।हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को कलेक्टर द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अदालत के फैसले को इस अदालत में चुनौती दी गई थी।उस समय सही तरीका यह था कि आवेदन को तब तक लंबित रखा जाए जब तक कि मामला अंतिम रूप न ले ले और उसे खारिज न किया जाए।अधिनियम की खंड 28 ए के तहत भूमि मालिकों द्वारा दायर आवेदन के फैसले के खिलाफ, भूमि मालिक को विवाद को अदालत में भेजने के लिए कलेक्टर को आवेदन दायर करने का अधिकार है।उस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर भी विचार नहीं किया गया था और केवल 'दायर' किया गया था।कलेक्टर का निर्णय पूरी तरह से कानून के प्रावधान के विपरीत है, इसलिए इसे दरकिनार कर दिया जाए और याचिकाकर्ता के आवेदन के नए सिरे से निर्णय के लिए मामले को वापस भेज दिया जा

(राजेश बिंदल, जे.)

(3) दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि याचिकाकर्ता को मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार था, हालांकि, इसकी खंड 28 ए (1) में प्रदान की गई कुछ सीमाओं के अधीन।

(4) पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और पेपर किताब का अध्ययन किया

(5) अधिनियम की खंड 28 ए के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैः

"28 क. न्यायालय के निर्णय के आधार पर मुआवजे की राशि का पुनर्निर्धारणः-

(1) जहां इस भाग के तहत किसी अधिनिर्णय में, न्यायालय आवेदक को खंड 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से अधिक मुआवजे की किसी भी राशि की अनुमति देता है, वहां खंड 4, उप-खंड (1) के तहत एक ही अधिसूचना द्वारा कवर की गई अन्य सभी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति और जो कलेक्टर के पुरस्कार से व्यथित हैं, वे अदालत के निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा, खंड 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन नहीं करने के बावजूद, यह अपेक्षा कर सकते हैं कि उन्हें देय मुआवजे की राशि अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि के आधार पर फिर से निर्धारित की जा सकती हैः

बशर्ते कि तीन महीने की अवधि की गणना करने में जिसके भीतर इस उप-धारा के तहत कलेक्टर को आवेदन किया जाएगा, जिस दिन अनुदान

घोषित किया जाएगा और अनुदान की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।

(2) कलेक्टर, उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, सभी इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस देने और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद जांच करेगा और आवेदकों को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक अनुदान देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसने उप-खंड (2) के तहत पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि मामला कलेक्टर द्वारा न्यायालय के निर्धारण के लिए भेजा जाए और खंड 18 से 28 के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे संदर्भ पर लागू होंगे जो वे खंड 18 के तहत किसी संदर्भ पर लागू होते हैं।"

(6) खंड 28 ए (1) के अवलोकन से पता चलता है कि जहां भूमि मालिक ने अधिनियम की खंड 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन दायर नहीं किया था और उसी अधिग्रहण के संदर्भ में अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजा कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से अधिक था, तो भूमि मालिक अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि के संदर्भ में उसे देय मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए कलेक्टर को आवेदन दायर कर सकता है।कुछ अवधि निर्दिष्ट की गई है जिसके दौरान इस तरह का आवेदन दायर किया जा सकता है।आवेदन प्राप्त होने के बाद, कलेक्टर इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदकों को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक पुरस्कार देता है।यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की खंड 28 ए (2) के तहत कलेक्टर द्वारा दिए गए पुरस्कार को प्रतिग्रहण करना नहीं करता है, तो उसे मुआवजे के निर्धारण के लिए मामले को अदालत में भेजने के लिए कलेक्टर को आवेदन दायर करने का अधिकार है।उस प्रक्रिया में खंड 18 से 28 के प्रावधान जहां तक हो सके लागू होने हैं।

(7) इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वी**.** रामकृष्ण राव बनाम द सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और अन्य पर विचार किया गया था |

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम में इसके अधिनियमन के 90 वर्षों के बाद किया गया संशोधन, अधिनियम की खंड 28 ए को जोड़ते हुए, भूमि मालिकों को कुछ सांत्वना प्रदान करने के उद्देश्य से था, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था,

लेकिन गरीबी, अज्ञानता और अन्य अक्षमताओं सहित विभिन्न कारणों से कलेक्टर के अनुदान पर विवाद करने और उच्च मुआवजे का दावा करने के लिए अधिनियम की खंड 18 के तहत आपत्तियां दायर नहीं कर सके। उन्हें राज्य दिए गए हैं।

1 2011 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 149

अन्य भूमि मालिकों के समान मुआवजे की मांग करने का अवसर, जिनकी भूमि का अधिग्रहण उसी अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।हालांकि, अधिनियम की खंड 28 ए का लाभ केवल उस भूमि मालिक के लिए उपलब्ध है जो अधिनियम की खंड 18 के तहत कलेक्टर को आपत्तियां दर्ज करने में समर्थ नहीं था। यह भी राय दी गई कि अधिनियम की खंड 28 ए (2) के तहत निर्णय के खिलाफ उपाय अधिनियम की खंड 28 ए (3) के तहत आवेदन दायर करना है, जिसमें विवाद को अदालत में संदर्भित करने की मांग की गई है।रिलायंस को भारत संघ बनाम प्रदीप कुमारी, (1995) 2 एस. सी. सी. 736 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर रखा गया था।रामकृष्ण राव के मामले (ऊपर) के फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ 9 और 11 नीचे दिए गए हैंः

"9. उपरोक्त पुनर्निर्मित प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए विधानमंडल के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है कि संविधान की प्रस्तावना और उसके अनुच्छेद 38,39 और 46 में निहित समानता का लक्ष्य वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, कम से कम उन लोगों को मुआवजे के भुगतान के मामले में जो राज्य, इसकी साधनों/एजेंसियों और यहां तक कि निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए अपनी भूमि से वंचित हैं।खंड 28 ए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में समानता के सिद्धांत के वैधानिक अवतार का भी प्रतिनिधित्व करती है।यह अधिनियम जो 1894 में अधिनियमित किया गया था और 90 वर्षों के बाद संशोधित किया गया था, उसमें समाज के एक बड़े वर्ग को वंचित करने की क्षमता है। उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत 'कृषि ' है।धारा 28 ए की योजना समाज के इस खंड को यह सुनिश्चित करके कुछ सांत्वना प्रदान करती है कि ऐसे भूमि मालिक जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई थी, लेकिन जो गरीबी, अज्ञानता और अन्य अक्षमताओं के कारण धारा 18 के तहत संदर्भ मांगने में दूसरों के साथ शामिल नहीं हो सके, उन्हें दूसरों के समान मुआवजे का दावा करने का अवसर मिले।इस खंड का उद्देश्य उसी अधिसूचना के तहत भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजे के भुगतान में असमानता को दूर करना है।इसे अलग तरह से कहने के लिए, यह खंड भूमि मालिक को एक मौका देती

है, जिसने अदालत द्वारा बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए खंड 18 के तहत आवेदन नहीं किया होगा, मुआवजे की राशि के पुनर्निर्धारण की मांग करने के लिए, यदि कोई अन्य समान रूप से स्थित भूमि मालिक अधिग्रहित भूमि का उच्च बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए संदर्भ न्यायालय को मनाने में सफल हो जाता है।इसलिए, खंड 28 ए की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो भूमि मालिक को अवसर देने के लिए कानून की नीति को आगे बढ़ाए, जो विभिन्न कारणों से कलेक्टर को स्थानांतरित करने में समर्थ नहीं हो सकता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1

अधिनियम की खंड 18 के तहत अधिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए संदर्भ देना यदि संदर्भ न्यायालय द्वारा अन्य भूमि मालिकों के कहने पर बाजार मूल्य में संशोधन किया जाता है, जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई है।बेशक, इस अवसर का लाभ निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन दाखिल करके उठाया जा सकता है।इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खंड 28 ए एक लाभकारी प्रावधान की प्रकृति में है जिसका उद्देश्य असमानता को दूर करना और असमर्थ और गरीब भूमि मालिकों को राहत देना है, जो अधिनियम की खंड 18 के तहत दीवानी न्यायालय में निर्देश के अधिकार का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं और ऐसे प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो कानून की नीति से असमर्थ आगे बढे

X X X X X X X X X

“11. यदि खंड 28 ए की उप-खंड (3) की व्याख्या मुआवजे के भुगतान के मामले में असमानता को दूर करने के प्रावधान को लागू करके प्राप्त किए जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जाती है, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जो खंड 28 ए (2) के तहत दिए गए अनुदान से संतुष्ट नहीं है, वह अधिनियम की खंड 3 (डी) में परिभाषित न्यायालय को संदर्भित करने के लिए खंड 28 ए (3) के तहत कलेक्टर को आवेदन कर सकता है और इस अधिकार को केवल इसलिए विफल नहीं किया जा सकता है क्योंकि खंड 28 ए (2) के तहत किए गए पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप आवेदक अन्य भूमि मालिकों के समान मुआवजा प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।खंड 28 ए (3) की सरल भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि एक व्यक्ति जिसने खंड 28 ए (2) के तहत दिए गए अनुदान को स्वीकार नहीं किया है, वह

मामले को अदालत में भेजने के अनुरोध के साथ कलेक्टर को आवेदन करने से वंचित है। बेशक, जिस न्यायालय को खंड 28 ए (3) के तहत निर्देश दिया गया है, उसे यह ध्यान रखना होगा कि जिस व्यक्ति ने खंड 18 के तहत निर्देश नहीं मांगा है, उसे उन लोगों को देय मुआवजे से अधिक नहीं मिल सकता है जिन्होंने उस खंड के तहत निर्देश मांगा था।"

(8) माननीय उच्चतम न्यायालय ने वी. रामकृष्ण राव बनाम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और अन्य मामले में अधिनियम की खंड 283 ए के दायरे पर आगे विचार किया। इसमें आगे यह राय दी गई है कि जिस न्यायालय को अधिनियम की खंड 28 ए (3) के तहत निर्देश दिया गया है, उसे यह ध्यान रखना होगा कि जिस व्यक्ति ने अधिनियम की खंड 18 के तहत निर्देश नहीं मांगा है, उसे उन लोगों को देय मुआवजे से अधिक नहीं मिल सकता है जिन्होंने उस खंड के तहत निर्देश मांगा था।

2 (2010) 10 एस. सी. सी. 650

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए मामले में, याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 23.5.1983 के माध्यम से किया गया था। कलेक्टर ने 17.3.1986 को अनुदान की घोषणा की।याचिकाकर्ता ने अधिनियम की खंड 18 के तहत आपत्तियां दर्ज नहीं कीं। अन्य भूमि मालिकों ने अधिनियम की खंड 18 के तहत आवेदन दायर किए, जिन्हें अदालत में भेजा गया।संदर्भ न्यायालय ने अपने दिनांक 30.11.1991 के निर्णय के माध्यम से, प्रति वर्ग गज 100/3 की दर से उसी अधिग्रहण के लिए देय मुआवजे का निर्धारण किया।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की खंड 283 ए के तहत कलेक्टर के समक्ष आवेदन दायर किया। इसे दाखिल करने के बारे में कोई विशिष्ट तिथि उपलब्ध नहीं है।याचिकाकर्ता को कलेक्टर द्वारा 10.3.1993 पर सुनवाई का अधिकार दिया गया था।कलेक्टर ने दिनांक 9.4.1993 (अनुलग्नक 3P3) के आदेश में दर्ज किया कि अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया कि सरकार ने संदर्भ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है।चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा जिस पुरस्कार पर भरोसा करने की मांग की गई थी, वह अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आवेदक/याचिकाकर्ता उस लाभ को प्राप्त करने का हकदार नहीं था।आवेदन को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा गया था। 9.4.1993 को पारित आदेश नीचे निकाला गया हैः

“प्रेम सिंह पुत्र मान सिंह ने खंड 28 ए के तहत यह आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है कि श्री आर.एन.सिंघल द्वारा दिए गए पुरस्कार दिनांक 30.11.91 को देखते हुए उनके मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। आर. एन. सिंघल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार।

आवेदक को खंड 28 ए (2) के तहत सुनवाई के लिए नोटिस दिया गया था। राजबीर सिंह, जनरल अटॉर्नी, 10.3.93 को उनकी ओर से मेरे सामने पेश हुए।राजबीर सिंह को सुना गया और उनका बयान दर्ज किया गया।अभिलेख की जांच की गई और यह पाया गया कि सरकार ने उस निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की है जिसके आधार पर आवेदन (एस. आई. सी. आवेदक) ने मुआवजे के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है।इस प्रकार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए अनुदान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसे देखते हुए आवेदक को खंड 28 ए का लाभ नहीं दिया जा सकता है। मैं अनुदान से सहमत हूँ।

कलेक्टर द्वारा दिया गया।आवेदक को सूचित किया जाए और फाइल को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा जाए।”

(10) निर्णय याचिकाकर्ता को दिनांकित 30.4.1993 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता अधिनियम की खंड 283 ए के तहत लाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए, कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं था, इसलिए आवेदन 'दायर' किया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता ने मुआवजे के निर्धारण के लिए विवादग्रस्त मामले को अदालत में भेजने के

लिए कलेक्टर को आवेदन दायर किया।ऐसा अधिकार अधिनियम की खंड 28 ए (3) के तहत भूमि मालिक को उपलब्ध है। उसी को भी खारिज कर दिया गया और कलेक्टर द्वारा आवेदन दायर किया गया।याचिकाकर्ता को 9.2.1995 पर यह उल्लेख करते हुए सूचना दी गई थी कि याचिकाकर्ता अधिनियम की खंड 28 ए (2) के तहत किसी भी लाभ का हकदार नहीं पाया गया था। खंड 28 ए (3) के तहत दायर आवेदन भी 'दायर' किए जाने के योग्य है।

(11) कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 9.4.1993 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अधिआदेश की खंड 28 ए (1) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन केवल इस कारण से दायर किया गया था कि संदर्भ न्यायालय का निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए भरोसा किया गया था, इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय था।ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से समझाया गया है।

केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नोएडा

बनाम यू. पी. राज्य 3.न्यायालय द्वारा व्यक्त राय यह है कि ऐसी स्थिति में कलेक्टर अधिनियम की खंड 28 ए के तहत आवेदन को तब तक लंबित रखने की अपनी शक्ति के भीतर होगा जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है।इसका प्रासंगिक पैरा नीचे निकाला गया हैः

"40. यह सच है कि एक बार जब संदर्भ न्यायालय मामले का फैसला करता है और मुआवजे को बढ़ाता है, तो एक व्यक्ति जो अन्यथा समान राहत के लिए पात्र है और जिसने संदर्भ नहीं मांगा है, वह अधिनियम की खंड 283 ए के तहत आवेदन कर सकता है। यदि उक्त प्रावधान के आवेदन के लिए शर्तों का पालन किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति उसी राहत का हकदार होगा जो संदर्भ और बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाले अन्य व्यक्तियों को दी गई है।लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि यदि संदर्भ न्यायालय मामले का फैसला करता है और राज्य या अधिग्रहण करने वाला निकाय मुआवजे की ऐसी बढ़ी हुई राशि को चुनौती देता है और मामला या तो लंबित है।

3 2009(1) एस. सी. सी. 754

उच्च न्यायालय या इस न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) के समक्ष, कलेक्टर अधिनियम की खंड 283 ए के तहत आवेदन को तब तक लंबित रखने के लिए अपनी शक्ति या अधिकार के भीतर होगा जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है।इसका कारण यह है कि मुआवजे को बढ़ाने के संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ने 'अंतिमता' प्राप्त नहीं की है और यह एक उच्च विचाराधीन समक्ष विचाराधीन है।"

(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भारत संघ बनाम मुंशी राम (मृत) में एल. आर. एस. और अन्य 4 द्वारा भी उल्लेख किया जा सकता है

।

(13) कानून के उपरोक्त उच्चारण को ध्यान में रखते हुए, इस परिस्थिति में कलेक्टर के लिए सही रास्ता यह था कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की खंड 28 ए के तहत दायर आवेदन को तब तक लंबित रखा जाए, जब तक कि मामला उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया जाता।हालाँकि, उन्होंने इसे अस्वीकार करना उचित समझा।

(14) हालांकि लिखित बयान में यह रुख अपनाने की मांग की गई है कि अधिआदेश की खंड 28 ए के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर समय की पाबंदी थी, हालांकि, कलेक्टर द्वारा 09.04.1993 पर पारित आदेश में यही कारण नहीं दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता को दिनांकित 30.04.1993 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था।रिकॉर्ड से कोई तथ्य सामने नहीं आया है या सुनवाई के समय यह दिखाने के लिए इंगित नहीं किया गया है कि अधिनियम की खंड 28 ए के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन समय से वर्जित था।(15) ऊपर वर्णित कारणों से, हमारे विचार में, आक्षेपित संचार संलग्नक पी5 को अलग रखा जाना चाहिए।तदनुसार आदेश दिया।याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की खंड 28 ए (3) के तहत दायर आवेदन के निर्णय के लिए मामले को कलेक्टर को वापस भेज दिया जाता है, ताकि याचिकाकर्ता को देय मुआवजे के निर्धारण के लिए विवादग्रस्त मामले को अदालत को भेजा जा सके।आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कलेक्टर द्वारा आवश्यक कार्य किया जाएगा।

(16) रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

A.Jain

4 2006(2) आर. सी. आर. (सिविल) 763

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

कमलेश

आनुवाद करता